खाद्यान्न भंडार

917. श्री रजनी रंजन साहू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में खाद्यान्न के भंडार में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान तिलहनों और कपास का कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 के अन्त में (अर्थात् 31 मार्च को) सार्वजनिक एजेंसियों के पास खाद्य भंडार में 5.54 मिलियन मीटरी टन की वृद्धि हुई है जो 1989-90 के 11.73 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1990-91 में 17.27 मिलियन मीटरी टन हो गया है ।

(ख) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में तिहलहनों और कपास का उत्पादन इस प्रकार रहा:--

जिन्स	इकाई	उत्पादन	
		1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
तिलहन	मिलियन मीटरी टन	16.75	19.10
कपास	170-170 कि०ग्रा० की लाख गांठें	114.1	100.0

दिल्ली-मुजफ्फरपुर के बीच नई रेल गाड़ी का चलाया जाना

918. श्री रजनी रंजन साहू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में दिल्ली-मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर-दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद

919. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने 1991-92 के खरीद मौसम के दौरान जो गेहूं की मात्रा खरीदी है वह पिछले वर्ष खरीदी गई मात्रा की तुलना में बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं की सरकारी खरीद में हुई इस कमी के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) और (ख) वर्तमान रबी विपणन मौसम 1991-92 के दौरान

19 जुलाई, 1991 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों के सहयोग से मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन 77.46 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की है जबकि पिछले समूचे रबी विपणन मौसम, 1990-91 के दौरान 110.74 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी।

मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और किसानों द्वारा बिक्री के लिये पेश किये गये उचित औसत किस्म के समस्त स्टाक को भारतीय खाद्य निगम/राज्य की एजेंसियों द्वारा खरीद लिया जाता है। किसान अपनी पैदावार सरकार द्वारा निर्धारित किये गये समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर खुले बाजार में बेचने के लिये स्वतंत्र हैं।

920. [*Transferred to 30th July, 1991*]

Starvation deaths in Orissa

921. SHRI RAM JETHMALANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the "Times of India" dated the 11th July, 1991 under the caption "Starvation deaths in Orissa confirmed";

(b) if so, whether Government had set up a judicial commission to look into the starvation deaths in the Kalahandi and Bolangir districts of Orissa during past year and the Commission has submitted its report to Government;

(c) if so, the findings thereof; and

(d) whether Government have taken any steps to check the recurrence of such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes, sir.

(b) and (c) Neither Central Government nor State Government of Orissa had set up any Judicial Commission. However, Orissa High Court had appointed a one man Commission to enquire into the allegation of starvation deaths and exploitation of tribals by landlords in Kalahandi and Bolangir Districts of Orissa during the past five years arising out of public interest litigation. The Commission has submitted its report to Orissa High Court.

(d) Various development programmes like Integrated Rural Development Programme, Jawahar Rozgar Yojana, National Drinking Water Mission including Accelerated Water Supply Programme and Drought Prone Area Programme are being implemented to improve the socio-economic condition of the rural masses.

तिलहनों का उत्पादन

922. श्री रणजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले वर्ष के दौरान तिलहनों का उत्पादन गत वर्षों की अपेक्षा अधिक हुआ है;

(ख) क्या उत्पादन 18.5 मिलियन टन आंका गया है;

(ग) यदि हां, तो तिलहनों के अधिक उत्पादन के कारण देश में खाद्य तेल आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और उनके मूल्य कम हो गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि उत्पादन अधिक होने के बावजूद उपभोक्ता खाद्य तेलों के मूल्यों से लाभान्वित नहीं हो पाये हैं; और

(ङ) क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये अधिक उत्पादन के लाभ उत्पादकों और उपभोक्ताओं को दिलाने हेतु तेल नीति में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिये आवश्यक